विशेष लेख -अंतिम भाग

ट्यूनीशिया, मिस्र और अरब जगत में भूचाल

एजाज अहमद विश्वप्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक एवं समाजशास्त्री हैं। उनका यह लेख **‘ऑटम ऑफ पेट्रियार्क’** शीर्षक से **‘फ्रंटलाइन’** के फरवरी अंक में प्रकाशित हुआ था। उसे **‘देश–विदेश’** ने हिंदी में प्रकाशित किया है। लेख का अनुवाद **ज्ञानेन्द्र** ने किया है। चूंकि हिंदी पाठकों तक इस महत्त्वपूर्ण लेख का अधिक से अधिक प्रसार हो सके, इसलिए हम ‘फ्रंटलाइन’ और ‘देश–विदेश’ के प्रति आभार प्रकट करते हुए इस लेख के सबसे महत्त्वपूर्ण अंशों को प्रकाशित कर रहे हैं।

घेराबंदी के काल में शाश्वत शहर - काहिरा

इस लेख को लिखते समय तक ख़बर है कि काहिरा में पोर्ट सईद तक मिस्र के छः शहरों में 20 लाख लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। 10 लाख लोग़ों के एक दिन और प्रदर्शन की योजना है, जिसे मिस्र के 82 वर्षीय तानाशाह मुबारक के लिए ‘प्रस्थान का दिन’ घोषित किया गया है। प्रदर्शनकारियों की संख्या देख कर तानाशाही स्तब्ध है। महज इसख्याल से कि दो दिन बाद ही शुक्रवार को फ़िर वह दोहराया जायेगा, जब हज़ारों लोग मस्जिदों में दोपहर की नमाज अदा करने के लिए एकत्र होंगे, सिके बाद उन्हें प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होने से नहीं रोका जा सकेगा। तानाशाही शासन हतप्रभ है। प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध पुलिस ने अब तक छिटपुट हिंसा का प्रयोग किया है। एक प्रदश्नन से स्तब और दूसरे से भयग्रस्त शासकों ने तथाकथित ‘मुबारक समर्थकों’ - सामान्य नागरिकों का वेश बदल कर आये सेना–पुलिस के जवान और भाड़े के गुंडों को तांडव की खुली छूट दे दी। पहले दिन थाह लेने के लिए छोटे पैमाने पर और दूसरे दिन कहीं ज़्यादा क्रूरतापूव्रक दमन–चक्र चलाया गया। हम नहीं कह सकते आगे क्या होगा।

प्रशासन के पास तैयारी के लिए समय और साधन दोनों मौजूद रहे हैं। मिस्र की राज्यसत्ता अरब जगत में अब तक सबसे शक्तिशाली रही है। नासिर के शसन काल में भी ऐसा ही था जब पश्चिमी ताकतों ने उससे किनाराकशी कर ली थी। सादात द्वारा इजराइल के साथ शांति समझौते पर दस्तखत किये जाने और मिस्र की अर्थव्यवस्था के पश्चिमी कारपोरेटों की लूट के लिए खोले जाने के बाद से मिस्र की राज्यसत्ता अरब राष्ट्रवाद की निंदा करने और उसकी जगह इजराइल से गठजोड़ करने के एवज में अमेरिका से 30 अरब डॉलर का इनाम हासिल कर चुकी है। मुक्तहस्त से दिये गये इस दान का सबसे बड़ा हिस्सा सैनिक बलों की झोली में गया है। मिस्र के पास 10 लाख से ज़्यादा आंतरिक सुरक्षा बल हैं जिसका वार्षिक बजट एक अरब डॉलर से ज़्यादा है जो कि अफ्रीकी और अरब जगत के मानकों से बहुत ही अधिक है। उमर सुलेमान जो अभी हाल तक आंतरिक सुरक्षा प्रमुख था और अब उपराष्ट्रपति भी है, बहुत संभव है कि मिस्र के अंददर सबसे प्रभावी शक्तियों का स्वामी है - मुबारक से भी ज़्यादा, क्योंकि मुबारक भी खु सुलेमान के तंत्र पर ही निर्भर करता रहा है।

जहां तक साम्राज्यवाद से संबंधों का सवाल है, सुलेमान अरब जगत में सीआईए द्वारा चलाई गयी कुख्यात ‘प्रत्यर्पण’ मुहिम की सबसे बड़ी कड़ी रहा है - इस कार्यक्रम के तहत अमेरिकी एजेंट किसी भी तरह का संदेह होने पर लोग़ों को दुनिया भर में कहीं से भी उठा लेते हैं और फ़िर गोपनीय तरीके से उन्हें पश्चिमी एशिया में अपनी पिट्ठू सरकारों को सौंप देते हैं, जो उनसे सूचनायें उगलवाने के लिए उत्पीड़ित करते हैं और कई मामलों मं उनकी हत्या करके उन्हें ‘गायब’ कर देते हैं। 1980 के दशक से ही, यानी 11 सितंबर के न्यूयार्क स्थित जुड़वां इमारतों पर हुए हमले और उसके बाद अमेरिका द्वारा ‘आतंक के खिलाफ़ युद्ध’ की औपचारिक घोषणा किये जाने के लगभग दो दशक पहले से ही सुलेमान की इस कार्यक्रम में केंद्रीय भूमिका रही है। यह ‘युद्ध’ दरअसल राष्टपति बुश के शासन काल के पहले से ही जारी है, हालांकि अफगानिस्तान और इराक पर आक्रमण के बाद से इसमें निश्चय ही तेज़ी आई है।

मुबारक और सुलेमान, दोनों ने मिल कर मिस्र को आतंकित किया है और एक के बिना दूसरा जीवित नहीं रह सकता। हुस्नी मुबारक जो पहले मिस्र की वायु सेना का प्रमुख था और अब औपचारिक रूप से मिस्र के सैनिक बलों का कमांडर इन चीफ़ है, सेना से कही ज़्याा आंतरिक सुरक्षा बलों पर भरोसा करता है और अलबरदेई समेत समूचा विपक्ष इस विभ्रम का शिकार है कि आंतरिक सुरक्षा बल भले ही मुबारक की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेना उनकी तरफ़ है और अंततोगत्वा उनको बचाने के लिए हस्तक्षेप करेगी। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन केवल तभी जब वाशिंगटन से हरी झंडी मिल जाये और अमेरिका भी शायद ऐसा करने से पहले इस पर सहमति हासिल करने के लिए तेल अबीब से दरख्वास्त करेगा। हम तो बस यही जानते हैं कि जैसे ही ट्यूनीशिया की बगावत ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप लिया और पूरे अरब गत को प्रभावित करने वाले नतीजे सामने आने लगे, तब मिस्र का सैन्य प्रमुख भागा–भागा वाशिंगटन गया और वहां पूरा हफ़्ता बिता कर वापस लौटा। जाहिर है कि वह पूर्वी तट की कड़कड़ाती ठंड के मौसम में वहां महज पिकनिक मनाने के लिए नहीं गया था। निस्संदेह वह वहां से आपातकालीन स्थितियों से निपटने की एक पूरी वैकल्पिक योजना लेकर लौटा था। हम नहीं जानते कि वे योजनाएं क्या हैं।

मिस्र में बगावत की चरम स्थिति आने पर वहां विशेष दूत के तौर पर फ्रांक जी विस्नर की नियुक्ति के पीछे भी यही तर्क काम कर रहा है जो लगभग 40 सालों से सीआईए और अमेरिकी राज्य के लिए काम कर रहा है। विस्नर पहले जांबिया में राजदूत रहा, फ़िर फिलीपीन्स, मिस्र और भारत में और अब अमेरिका के पक्ष में दबाव बनाने (लॉबिंग) वाली एक कंपनी पेट्टन बोग्स के लिए काम करता है। पेट्टन बोग्स की वेबसाइट पर लिखा है - ‘हमने मिस्र की सेना और आर्थिक विकास एजेंसी को सलाह देने तथा यूरोप और अमेरिका में मिस्र की सरकार की ओर से दायर याचिकाओं की पैरवी और मध्यस्थता का काम किया है। हमारे वकील मिस्र के कुछ अगुआ व्यावसायिक परिवारों और उनकी कंपनियों का भी प्रतिनिधित्व करते हें तथा हम इन कपनियों द्वारा सचालित तेल, गैस और दूरसंचार ढांचे के विकास जैसी परियोजनाओं में उनकी ओर से पैरवी करते रहे हैं...हमने अमेरिका के विदेशी सैन्य बिक्री अधिनियम के तहत किये गये सैनिक बिक्री समणैतों में होने वाले ठेका–विवादों को निपआया है और क्षतिपूर्ति के मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभायी है।’

वेबसाइट आगे कहती है - ‘अपने अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों (क्लाइन्टों) की सहायता के लिए कंपनी मध्यपूर्व और भारत के बारे में राजदूत विस्नर की विशेषज्ञता का इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक रहती है।’

इस तरह मिस्र में अमेरिका का विशेष दूत ही दुनिया ीार में मिस्र की राज्यसत्ता के रिश्ते, कानून और वाणिज्यिक मामले का भी प्रतिनिधि है। साथ ही वह एक ऐसा व्यक्ति है जो सीआईए, अमेरिकी गृह मंत्रालय और अमेरिकी कारपोरेट - तीनों के प्रति अपने भीतर समान रूप से निष्ठा समोये हुए है। इसके अलावा इस बगावत के बारे मे मिस्र की सरकार की कार्रवाइयों की निगरानी करने वाला अमेरिकी सरकार का प्रतिनिधि भी वही है।

हम जानते हैं कि इजराइल के धुर दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मुबारक को सत्ता से हटाये जाने के खिलाफ़ अपनी टांग अड़ा दी है और हम यह भी जानते हैं कि वाशिंगटन के लिए 20 लाख प्रदर्शनकारियों की आवाज़ की तुलना में नेतन्याहू की बात कहीं ज़्यादा मायने रखती है। इजराइल के सबे उदारादी अख़बार हारेत्ज में आरी शावी के निम्नलिखित शब्दों को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि कि न सिर्फ़ नेतन्याहू बल्कि पूरा इजराइली बुद्धिजीवी समुदाय मिस्र में एक सफल बगावत के बारे में सोच कर कैसे बेचैन हो उठता है–

‘60 सालों तक अमेरिकी साम्राज्य ने दुनिया में स्थायित्व, शांति और समृद्धि कायम रखी। मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा अमेरिकी साम्राज्य की ताकत को कम करके आंक रहे हैं। हुस्नी मुबारक जिसने हमेशा अमेरिका के साथ वफ़ादारी की, अरब जगत में स्थायित्व को बढ़ावा दिया और मध्य–मार्ग को प्रोत्साहित किया, ओबामा द्वारा उसके साि किया गया विश्वासघात महज एक नरमपंथी मिस्री राष्ट्रपति के साथ विश्वासघात नहीं बल्कि तीसरी दुनिया में अमेरिका के हर रणनीतिक सहयोगी के साथ विश्वसघात का प्रतीक है। समूचे एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के नेताओं की निगाह अब इस पर टिकी है कि वाशिंगटन और काहिरा के बीच क्या चल रहा है।’

हम यह जानते हैं कि महमूद अब्बास जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण का असंवैधानिक राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तव में इजराइल का पिट्ठू है। उसने मिस्र के तानाशाह मुबारक के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए उसे फ़ोन किया था। इजराइली सरकार और फिलिस्तीनी प्राधिकरण मुबारक को लाखों मिस्रवासियों के गुस्से की आग से बचाने के लिए मिल कर कोशिश कर रहे हैं। हम आवाक हैं।

मिस्र के लाखों प्रदर्शनकारी इन्हीं सब के खिलाफ़ हैं। अचानक शुरू हुआ यह आंदोलन काहिरा में कुछ हज़ार लोगों के विरोध–प्रदर्शन से बढ़ कर दो हफ़्ते से भी कम समय में काहिरा से सिकन्दरिया तक, नील डेल्टा स्थित विभिन्न शहरों में बिना नेतृत्व या केंद्र के 20 लाख से ज़्यादा लोगों के विराट प्रदर्शन में बदल गया। निश्चित तौर पर यह जनता का विराट स्वत:स्फूर्त आंदोलन का नाम दिये जाने लायक है। यह आत्मविश्वास कि वे साम्राज्यवादी के वैश्विक गठजोड़ और उसके साथ–साथ देश के विस्तृत और शक्तिशाली दमनतंत्र और बर्बरता का भी मुकाबला कर सकते हैं, उनका भोलापन ही लगता है। लेकिन फ़िर भी इस स्वत:स्फूर्तता और भोलेपन की एक ठोस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है।

अधिकांश मिस्रवासियों के लिए अरब स्वाभिमान और अरब राष्ट्रवाद का पूरा इतिहास फिलीस्तीन के सवाल पर केंद्रित रहा है और उसके शसकों द्वारा इजराइल के साि संश्रय के तीन दशकों से भी लंबा इतिहास उनके मन में शर्म और गुस्से के रूप में दफ़्न है।

हाल के वर्षों में, सन् 2000 में ूसरे इन्तिफाा के शुरू होने के बाद से यह भावना फिलीस्तीन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने वाली बहुत–सी कार्रवाइयों के रूप में अभिव्यक्त हुई है। इसी तरह, उनके शसकों द्वारा अपने साम्राज्यवादी आकाओं के सामने निर्लज्ज आत्मसमर्पण को लेकर भी उनके मन में लंबे सय से शर्म और गुस्से की आग सुलग रही है और 2003 में इराक पर हुए हमले के बाद यह कई बगवती कार्रवाइयों के रूप में अभिव्यक्त हुई है। लेबनानी हिजबुल्ला संगइन के नेता नसरल्ला जिन्होंने ट्यूनीशिया और मिस्र की एकदम धर्मनिरपेक्ष बगावत के फैलने के साथ ही उसका स्वागत किया, 2006 में इजराइल के लीबिया पर हमले के बाद से मिस्र के लिए भी देशी नायक बन चुके हैं, इसलिए नहीं कि मिस्र की जनता (जो बहरहाल सुन्नी है) ने अचानक उग्र श्यिा इस्लामवाद अपना लिया, बल्कि इसलिए कि लेबनानी राष्ट्र की ओर से हिजबुल्ला ने इजराइल के खिलाफ़ कड़ा प्रतिरोध किया था।

मिस्र का मज़दूर वर्ग भी कभी पूरी तरह निष्क्रिय नहीं रहा है। सरकार द्वारा मन के तमाम प्रयासों के बावजूद आज मिस्र के लगीाग 28 प्रतिशत मज़दूर संगठित हैं जिनका बहुमत सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत है। इस संदर्भ में ‘सामाजिक आंदोलन’ शब्द का प्रयोग किया जाये या नहीं, इसे लेकर मैं आश्वस्त नही हूं, लेकिन स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रोफ़ेसर जोल बीनीन जब मिस्र के मज़दूर आंदोलन को ‘...द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर में अरब जगत का सबसे बड़ा सामाजिक आंदोलन’ करार देते हैं तो उनकी बात ठीक लगती है। फ़रवरी 2010 में अंतराष्ट्रीय शंति के कारनेगी इंडोवमेंट और इंटरनेशनल पीस द्वारा आयोजित संगोष्ठी में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के मुताबिक 2004 के बाद मिस्र के मज़दूरों के 3000 से भी ज़्यादा विरोध–प्रदर्शन हुए हैं। रिपोर्ट आगे कहती है कि इसके सामने ‘मिस्र में हुए राजनीतिक विरोध–प्रदर्शनों की संख्या और परिणाम बिल्कुल बौने नज़र आते हैं।’

1980 और 1990 के दशक में मिस्र के मज़दूर आंदोलन को पुलिस के बर्बर दमन का सामना करना पड़ा। 1989 की स्टील मिलों की हड़ताल के वक्त शांतिपूर्ण हड़ताल में भाग लेने वालों पर गोलियां चलाई गईं। 1994 में भी कपड़ा मिलों में हुई हड़तालों का बर्बरता से दमन किया गया। लेकिन दिसंबर 2006 से लगातार अब तक मिस्र 1946 के बाद की सबसे बड़ी और सबसे टिकाऊ हड़तालों का गवाह रहा है। ये हड़तालें मिस्र के नील नदी के डेल्टा में स्थित कसबे महल्ला में कपड़ा मज़दूरों की हड़ताल के बाद भड़क उठी थीं जहां पश्चिमी एशिया के सबसे ज़्यादा 28000 मज़दूर रहते हैं। सर्व–अरब राष्ट्रवाद और मज़दूर वर्ग के जुझारूपन का यह संयोग ही वह भौतिक आधार है जिसके कारण स्वत:स्फूर्त जन–उभार संभव हो सका।

(समाप्त)